



Only & Only NCERT
इसे कर लिया तो NCERT मुट्ठी में...

NCERT MCQs

भारतीय राजव्यवस्था
एवं प्रशासन

Class 6-12 (Old+New)

UPSC, State PSCs

एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी...

Only & Only NCERT
इसे कर लिया तो NCERT मुट्ठी में...

NCERT MCQs

भारतीय राजव्यवस्था
एवं प्रशासन

Class 6-12 (Old+New)

UPSC, State PSCs

एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी...

Only & Only NCERT
इसे कर लिया तो NCERT मुट्ठी में...

NCERT MCQs

भारतीय राजव्यवस्था
एवं प्रशासन

Class 6-12 (Old+New)

UPSC, State PSCs

एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी...

लेखक
अजीत कुमार, विकास कुमार सिंह
सम्पादक
राजेश राजन

 arihant

अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड



अरिहन्त पब्लिकेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड

सर्वाधिकार सुरक्षित

卐 © प्रकाशक

इस पुस्तक के किसी भी अंश का पुनरुत्पादन या किसी प्रणाली के सहारे पुनर्प्राप्ति का प्रयास अथवा किसी भी तकनीकी तरीके—इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या वेब माध्यम से प्रकाशक की अनुमति के बिना वितरण नहीं किया जा सकता है। 'अरिहन्त' ने अपने प्रयास से इस पुस्तक के तथ्यों तथा विवरणों को उचित स्रोतों से प्राप्त किया है। पुस्तक में प्रकाशित किसी भी सूचना की सत्यता के प्रति तथा इससे होने वाली किसी भी क्षति के लिए प्रकाशक, सम्पादक, लेखक अथवा मुद्रक जिम्मेदार नहीं हैं।

सभी प्रतिवाद का न्यायिक क्षेत्र 'मेरठ' होगा।

卐 रजि. कार्यालय

'रामछाया' 4577/15, अग्रवाल रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली- 110002

फोन: 011-47630600, 43518550

卐 मुख्य कार्यालय

कालिन्दी, टी०पी० नगर, मेरठ (यूपी)— 250002 फोन: 0121-7156203, 7156204

卐 शाखा कार्यालय

आगरा, अहमदाबाद, बरेली, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, झाँसी, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर तथा पुणे

PO No : TXT-XX-XXXXXXX-X-XX

PUBLISHED BY ARIHANT PUBLICATIONS (INDIA) LTD.

'अरिहन्त' की पुस्तकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.arihantbooks.com पर लॉग इन करें या info@arihantbooks.com पर सम्पर्क करें।

Follow us on...    



आपकी सफलता हमारी प्रतिबद्धता...

“अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ फिर ‘आईएस’ का सपना आँखों में सजाओ”

सिविल सेवा परीक्षा भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित, कठिन एवं चुनौतीपूर्ण परीक्षा है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी न केवल उच्च पद एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, बल्कि सिविल सेवक के रूप में देश एवं समाज के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।

भारत में सिविल सेवा की परीक्षा इसलिए भी कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाती है कि इसमें “कितना पढ़ना है” से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है “क्या पढ़ना है” अर्थात् इस परीक्षा में सफल होने के लिए प्रामाणिक एवं प्रासंगिक अध्ययन-सामग्री का अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है।

सफल अभ्यर्थियों के अनुभवों तथा विगत वर्षों के प्रश्न-पत्रों के विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ है कि इस परीक्षा में **NCERT की पुस्तकों** का विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हीं पुस्तकों को आधार बनाकर सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को परीक्षा में पूछा जाता है। **NCERT के तथ्यों** से प्रत्येक वर्ष सीधे प्रश्न पूछे जा रहे हैं।

इसके साथ-ही-साथ NCERT की पुस्तकों में **बेसिक कॉन्सेप्ट्स** बहुत ही सरल तरीके से समझाए गए हैं, जोकि विषय सम्बन्धी ज्ञान को और मजबूत बनाते हैं।

NCERT पुस्तकों के अध्ययन को आसान तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु ‘अरिहन्त पब्लिकेशन्स’ द्वारा ‘**NCERT MCQs**’ सीरीज तैयार की गई है। इस सीरीज में कक्षा 6 से 12 तक की पुरानी व नई **NCERT का कवरेज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों** के रूप में किया गया है।

पुस्तक में प्रश्नों का स्तर सिविल सेवा एवं विभिन्न लोक सेवा आयोगों की प्रारम्भिक परीक्षाओं के अनुरूप रखा गया है। इस पुस्तक में **प्रश्नों को अध्यायवार रूप** में रखा गया है, जिससे अभ्यर्थी को NCERT पुस्तक के सम्बन्धित विषय के सम्पूर्ण अध्ययन का ज्ञान प्राप्त हो सके। पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में NCERT की कक्षा के अनुसार पुस्तकों का विवरण तथा प्रत्येक प्रश्न में कक्षा आदि का स्रोत दिया गया है, जिससे प्रश्नों का क्रम विषय अनुसार बन सके। प्रश्नों के हल के साथ उनकी **विस्तृत एवं तथ्यपरक व्याख्या** भी दी गई है, जो आपके अध्ययन को बेहतर बनाने में सहायक होगी। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह शत-प्रतिशत NCERT की पुस्तकों पर आधारित है।

पुस्तक के अन्त में **तीन प्रैक्टिस सेट्स** दिए गए हैं। इनमें से अधिकांश प्रश्न विगत वर्षों की सिविल सेवा एवं विभिन्न लोक सेवा आयोगों की प्रारम्भिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस पुस्तक को गुणवत्तापूर्ण बनाया गया है, जिससे यह सम्पूर्ण सीरीज निश्चय ही आपकी तैयारी में रामबाण का कार्य करेगी।

इस सीरीज को पूरा करने में विशेषज्ञों की एक टीम ने उत्साह के साथ कार्य किया है। इस पुस्तक के संकलन में विशेषज्ञों के साथ-साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट टीम का भी विशेष योगदान रहा, जिसमें मोना यादव (प्रोजेक्ट मैनेजर), दिव्या गुसाई (प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर), प्रीति रंधावा, मीनाक्षी, सुशील (प्रूफ रीडर्स), विनय शर्मा, कमल किशोर (डीटीपी ऑपरेटर) और शानू एवं मजहर (कवर एवं इनर डिजाइनर) प्रमुख हैं।

आशा है कि सिविल सेवा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी इस पुस्तक का अध्ययन कर अपने लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त करेंगे। आपके उपयोगी सुझाव सदैव हमें बेहतर संस्करण बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इसलिए आप हमें अपने सुझाव अवश्य भेजें, जिनके आधार पर हम पुस्तक के आगामी संस्करण को और भी बेहतर बना सकें।

लेखक

विषय-सूची

अध्याय 1.	संवैधानिक विकास	1-5
अध्याय 2.	संविधान निर्माण की प्रक्रिया	6-10
	<ul style="list-style-type: none">• संविधान का परिचय• संविधान सभा का गठन/संविधान निर्माण	
अध्याय 3.	भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मुख्य विशेषताएँ	11-17
	<ul style="list-style-type: none">• प्रस्तावना• संविधान की विशेषताएँ	
अध्याय 4.	संघीय क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन	18-22
अध्याय 5.	नागरिकता	23-24
अध्याय 6.	मौलिक अधिकार	25-33
अध्याय 7.	राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व	34-38
अध्याय 8.	मौलिक कर्तव्य	39-40
अध्याय 9.	संघ की कार्यपालिका	41-51
	<ul style="list-style-type: none">• भारतीय प्रशासन एवं सरकार• राष्ट्रपति• उपराष्ट्रपति• प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्• मंत्रिमंडलीय सचिवालय/प्रशासनिक सेवाएँ	
अध्याय 10.	केंद्रीय विधायिका	52-63
	<ul style="list-style-type: none">• राज्यसभा• लोकसभा• संसदीय विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ• संसदीय कार्यवाही• संसद की कार्यप्रणाली• विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ• संसदीय समितियाँ	

अध्याय 11. राज्य की कार्यपालिका	64-66
<ul style="list-style-type: none">• राज्यपाल• मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	
अध्याय 12. राज्य की विधायिका	67-70
<ul style="list-style-type: none">• विधानसभा• विधान परिषद्• विधानमंडल की शक्तियाँ एवं कार्य	
अध्याय 13. न्यायपालिका	71-80
<ul style="list-style-type: none">• सर्वोच्च न्यायालय• उच्च न्यायालय• अधीनस्थ न्यायालय	
अध्याय 14. संघवाद एवं केंद्र-राज्य संबंध	81-85
<ul style="list-style-type: none">• संघवाद• केंद्र-राज्य संबंध	
अध्याय 15. आपातकालीन उपबंध	86-88
अध्याय 16. लोक सेवाएँ एवं राजभाषा	89-91
<ul style="list-style-type: none">• भारत में लोक सेवाएँ• राजभाषा	
अध्याय 17. विभिन्न समुदायों के लिए विशेष उपबंध	92-94
अध्याय 18. स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज)	95-101
<ul style="list-style-type: none">• पंचायती राज व्यवस्था : विकेंद्रीकरण• नगर निगम एवं नगरपालिका• राज्य वित्त आयोग/योजना समितियाँ• जिला प्रशासन एवं सहकारिता	

अध्याय 19. निर्वाचन प्रणाली एवं दलीय व्यवस्था	102-111
<ul style="list-style-type: none">• निर्वाचन प्रणाली• निर्वाचन आयोग• चुनाव सुधार• दलीय व्यवस्था• दबाव समूह	
अध्याय 20. कुछ राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान	112-114
अध्याय 21. संवैधानिक एवं गैर-संवैधानिक संस्थाएँ	115-118
<ul style="list-style-type: none">• संवैधानिक संस्थाएँ• गैर-संवैधानिक संस्थाएँ• अन्य मानवाधिकार संस्थाएँ	
अध्याय 22. संविधान संशोधन	119-121
अध्याय 23. राजनीति सिद्धांत एवं मूल अवधारणाएँ	122-130
<ul style="list-style-type: none">• राजनीतिक सिद्धांत• मूल अवधारणाएँ	
अध्याय 24. विविध (विदेश नीति/गुटनिरपेक्षता/राष्ट्रीय प्रतीक)	131-137
<ul style="list-style-type: none">• विदेश नीति/गुटनिरपेक्षता• राष्ट्रीय प्रतीक	
प्रैक्टिस सेट्स	141-150
<ul style="list-style-type: none">• प्रैक्टिस सेट 1• प्रैक्टिस सेट 2• प्रैक्टिस सेट 3	

संवैधानिक विकास

Old NCERT Class XI भारतीय संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण मोड़

1. 1773 के नियामक अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

1. इसके अंतर्गत कलकत्ता प्रेसीडेंसी में एक सरकार की स्थापना की गई।
2. इस सरकार में गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद् के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे।
3. इसने ब्रिटिश ताज को बंबई में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना के लिए अधिकृत किया, जिसका क्षेत्र बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक विस्तृत था।
4. इस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल एवं उसकी परिषद् पर कई अंकुश लगाए।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) केवल 3 (d) 2, 3 और 4

➤ उत्तर (c)

व्याख्या 1773 के नियामक अधिनियम (रेग्यूलेटिंग एक्ट) के संबंध में कथन (3) असत्य है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ताज को बंबई में नहीं, बल्कि कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना के लिए अधिकृत किया था।

इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ई. में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 'सर एलिजाह इम्पे' को इस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा रॉबर्ट चैंबर्स, स्टीफन सीजर एवं जॉन हाइड तीन अन्य न्यायाधीश बनाए गए। इस न्यायालय का कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक विस्तृत था।

2. दिए गए अधिनियमों में कौन-से अधिनियम 'चार्टर एक्ट' के नाम से जाने जाते हैं?

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

- (a) 1833 का अधिनियम (b) 1853 का अधिनियम
(c) 1858 का अधिनियम (d) 'a' और 'b' दोनों

➤ उत्तर (d)

व्याख्या 1833 व 1853 दोनों ही अधिनियम 'चार्टर एक्ट' के नाम से जाने जाते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 1793 ई. से 1853 ई. के बीच चार चार्टर एक्ट (1793, 1813, 1833 व 1853 का अधिनियम) पारित किए गए। इन चार्टर एक्ट के माध्यम से भारतीय प्रशासन में समय-समय पर परिवर्तन का आज़ा-पत्र जारी किया गया।

3. सूची-I को सूची-II के साथ सही सुमेलित कीजिए।

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

सूची-I (अधिनियम)	सूची-II (प्रावधान)
A. 1833 का चार्टर अधिनियम	1. विधि निर्माण की शक्ति सपरिषद् गवर्नर-जनरल से सन्निहित
B. 1853 का चार्टर अधिनियम	2. गवर्नर-जनरल की परिषद् में 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई
C. 1858 का अधिनियम	3. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया
D. 1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम	4. गवर्नर-जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति

कूट

- A B C D
(a) 1 2 3 4
(b) 2 3 4 1
(c) 3 4 1 2
(d) 4 1 2 3

➤ उत्तर (a)

व्याख्या सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है।

1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए विधि निर्माण का एकाधिकार सपरिषद् गवर्नर-जनरल में सन्निहित कर दिया गया। परिषद् के सदस्यों की संख्या 4 रखी गई, जिसमें एक विधि-सदस्य होता था।

1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर-जनरल की परिषद् में जब वह विधायिका के रूप में कार्य करती हो 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। इन 6 नए सदस्यों में मद्रास, बंबई, बंगाल तथा पश्चिमोत्तर प्रांतों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि और एक मुख्य न्यायाधीश व एक कनिष्ठ न्यायाधीश होते थे।

1858 के अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा उनके अधिकार को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य (भारतीय सचिव) को दे दिया गया।

1861 के भारतीय परिषद् अधिनियम के द्वारा गवर्नर-जनरल को आपात स्थिति में परिषद् की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया।

NCERT MCQs • संवैधानिक विकास 02

4. 1861 के भारतीय परिषद् अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

1. इस अधिनियम में गवर्नर-जनरल की परिषद् में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई, जिनका कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया।
2. इस अधिनियम में उपबंध किया गया कि भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव पर सपरिषद् भारत सचिव के माध्यम से महारानी की स्वीकृति आवश्यक थी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर (c)

व्याख्या 1861 के भारतीय परिषद् अधिनियम के संदर्भ में कथन (1) और (2) दोनों सत्य हैं। भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861 में पहली बार गवर्नर-जनरल की परिषद् में सदस्यों की संख्या में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया। भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव पर सपरिषद् भारत सचिव के माध्यम से महारानी की स्वीकृति को इस अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया।

5. निम्न कथन (A) व कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

कथन (A) 1892 के भारतीय परिषद् अधिनियम में पहली बार विधान परिषदों में वित्तीय विषयों पर प्रश्न पूछने के लिए नियम बनाने का अधिकार गवर्नर-जनरल को दिया गया।

कारण (R) गवर्नर-जनरल द्वारा प्रश्न पूछने के संदर्भ में बनाए गए नियमों पर भारत सचिव की परिषद् की सहमति अनिवार्य थी।

कूट

- (a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
- (b) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (c) A सही है, किंतु R गलत है।
- (d) A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर (b)

व्याख्या कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परंतु कारण (R), कथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892 में पहली बार विधान परिषदों में वित्तीय विषयों पर प्रश्न पूछने के संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार गवर्नर-जनरल को दिया गया, किंतु नियमों पर सपरिषद् भारत सचिव की सहमति अनिवार्य थी।

इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार कर 8 से 20 नए सदस्य जोड़े गए, जिनमें 40% सदस्य गैर-सरकारी थे।

6. ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी?

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT) (MPPSC Pre 2019)

- (a) 1892 का भारतीय परिषद् अधिनियम
- (b) 1919 का भारतीय शासन अधिनियम
- (c) 1935 का भारतीय शासन अधिनियम
- (d) 1909 का भारतीय परिषद् अधिनियम

उत्तर (d)

व्याख्या भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 के माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत परिषद् में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों को वर्ग, समुदाय तथा हितों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक् निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई। निर्वाचक मंडल की सदस्यता हेतु आय, संपत्ति तथा शैक्षणिक योग्यता को पैमाना मानकर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई। इसे वर्ष 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है।

7. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 के संबंध में सत्य नहीं है?

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

- (a) केंद्रीय विधान परिषद् में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई, जिसमें 4 प्रकार के सदस्य यथा-पदेन, मनोनीत सरकारी, मनोनीत गैर-सरकारी तथा निर्वाचित सदस्य शामिल थे।
- (b) प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया।
- (c) विधान परिषद् के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया।
- (d) विधान परिषद् के सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने का अधिकार प्रदान किया गया।

उत्तर (c)

व्याख्या भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 के संदर्भ में कथन (c) सत्य नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषदों के कार्यों एवं अधिकारों में वृद्धि की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार विधान परिषद् के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, स्थानीय संस्थाओं को कर्ज देने, अतिरिक्त अनुदान देने तथा नए कर लगाने से संबंधित प्रस्तावों को प्रस्तावित करने का अधिकार प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त बजट स्वीकार करने से पूर्व बजट की विवेचना करने, सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने तथा उन पर मत-विभाजन की मांग करने का अधिकार भी दिया गया।

8. भारतीय शासन अधिनियम, 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन किया गया?

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

- (a) द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन
- (b) गवर्नर-जनरल परिषद् को एक सदन माना गया
- (c) केंद्रीय विधानमंडल के निर्वाचक मंडल में परिवर्तन
- (d) केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या में कमी

उत्तर (a)

व्याख्या भारतीय शासन अधिनियम, 1919 के अंतर्गत सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसमें प्रथम सदन राज्य परिषद् तथा दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा थी।

राज्य परिषद् में 60 सदस्य होते थे, जिनमें से 33 का निर्वाचन होता था तथा 27 सदस्य मनोनीत होते थे। केंद्रीय विधानसभा में कुल 145 सदस्य होते थे, जिनमें से 104 सदस्य निर्वाचित तथा 41 सदस्य मनोनीत होते थे। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची के विषयों पर विधि निर्माण अथवा उसे अस्वीकार करने का अधिकार था।

9. 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन-सा कथन असत्य है?

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

- (a) केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर-जनरल को प्राप्त था।

NCERT MCQs • संवैधानिक विकास 03

- (b) बजट को दो भागों में बाँटा जाता था। पहला जिस पर सदस्य मतदान कर सकते थे तथा दूसरा जिस पर सदस्य मतदान नहीं कर सकते थे।
- (c) सदस्य कुल खर्च के $\frac{2}{3}$ पर मतदान कर सकते थे, जबकि $\frac{1}{3}$ भाग पर वे मतदान नहीं कर सकते थे।
- (d) प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि बनाने का अधिकार था, किंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकार के कारण सीमित हो गए थे।

► उत्तर (c)

व्याख्या 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के संबंध में कथन (c) असत्य है, क्योंकि 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य कुल खर्च (बजट) के केवल $\frac{1}{3}$ भाग पर ही मतदान कर सकते थे, शेष $\frac{2}{3}$ भाग पर उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस अधिनियम के मतदान के आधार पर बजट को दो भागों में विभाजित किया गया था।

पहला भाग, जिस पर विधानमंडल के सदस्य मतदान कर सकते थे तथा दूसरा भाग वह था, जिस पर वह मतदान नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त जिन विषयों पर उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त था, उन विषयों पर भी गवर्नर-जनरल को यह अधिकार प्राप्त था कि सदस्यों द्वारा अस्वीकृत किए गए विषयों को अपने कर्तव्यपालन के आधार पर वह पुनर्जीवित कर सके।

10. भारत शासन अधिनियम, 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (Chap 1, Class-XI, Old NCERT) (IAS Pre 2012)

- 1 प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था
 2. मुसलमानों के लिए पृथक् सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल
 3. केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3 (c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

► उत्तर (c)

व्याख्या भारत शासन अधिनियम, 1919 के संदर्भ में कथन (1) और (3) सत्य हैं। भारत शासन अधिनियम, 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन से अभिप्राय ऐसी शासन प्रणाली से है, जिसमें उत्तरदायी तथा अनुत्तरदायी दोनों तत्त्वों का समावेश किया गया हो।

भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र की कुछ विधायी शक्तियों का हस्तांतरण प्रांतों को किया गया। कार्यों का वितरण केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों में किया गया।

कथन (2) असत्य है, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक् सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 में की गई थी।

11. भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित अधिनियम पर आधारित है? (Chap 1, Class-XI, Old NCERT) (IAS Pre 2012)

- (a) मार्ले मिटो सुधार, 1909
 (b) मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, 1919
 (c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
 (d) भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

► उत्तर (c)

व्याख्या भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित है, जिसे भारत के

संविधान ने अपनाया। इस अधिनियम में शासकीय कार्यों को तीन सूचियों में सूचीबद्ध किया गया। संघ सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 तथा समवर्ती सूची में 36 विषय थे। संघीय सूची में केंद्र सरकार को तथा प्रांतीय सूची में प्रांतीय सरकार को अनन्य क्षेत्राधिकार दिया गया। समवर्ती सूची पर केंद्र तथा प्रांतों को कानून बनाने का समान अधिकार था।

12. 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं? (Chap 1, Class-XI, Old NCERT) (IAS Pre 2018)

- (a) संघीय विधानपालिका को (b) प्रांतीय विधानमंडल को
 (c) गवर्नर-जनरल को (d) प्रांतीय गवर्नरों को

► उत्तर (c)

व्याख्या 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ गवर्नर-जनरल को दी गई थीं। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की स्थापना कर संघीय विषयों को संरक्षित तथा हस्तांतरित में वर्गीकृत किया गया था। संरक्षित विषयों पर गवर्नर-जनरल को स्वविवेक पर आधारित शक्तियाँ प्राप्त थीं। हस्तांतरित विषयों पर मंत्रिपरिषद् को नियंत्रण प्राप्त था। मंत्रिपरिषद् संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी।

13. भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। (Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

1. इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थीं।
 2. इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली का प्रस्ताव दिया गया था।
 3. इस अधिनियम ने शासकीय कार्यों को तीन सूचियों-संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभक्त किया।
 4. संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 58 थी।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं?
- (a) 1 और 2 (b) 2 और 3
 (c) 1, 2 और 3 (d) 2, 3 और 4

► उत्तर (c)

व्याख्या भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के संबंध में कथन (1), (2) और (3) सही हैं।

1935 का भारतीय शासन अधिनियम, भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे विस्तृत दस्तावेज था। इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थीं।

इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई।

संघ की दो इकाइयाँ थी-ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। इसके तहत प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई तथा इसके साथ ही केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन-संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया।

कथन (4) सही नहीं है, क्योंकि भारतीय शासन अधिनियम, 1935 की संघ सूची में 59, राज्य सूची में 54 तथा समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे।

14. भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता था, जब तक कि वह

- (a) दोनों सदनों द्वारा पारित न हो। (Chap 1, Class-XI, Old NCERT)
 (b) दोनों सदनों द्वारा पारित तथा गवर्नर-जनरल द्वारा स्वीकृत न हो।
 (c) दोनों सदनों द्वारा पारित तथा ताज द्वारा स्वीकृत न हो।
 (d) दोनों सदनों द्वारा पारित तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत न हो।

► उत्तर (b)

NCERT MCQs • संवैधानिक विकास 04

व्याख्या भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत कोई भी विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता था, जब तक वह दोनों सदनों द्वारा पारित तथा गवर्नर-जनरल द्वारा स्वीकृत न हो। किसी विधेयक के संबंध में मतभेद होने की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान था। गवर्नर-जनरल को यह शक्ति प्राप्त थी कि वह संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता था।

15. 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है?

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

1. संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 6 न्यायाधीश होते थे।
2. संघीय न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय था, जिसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त थी।

कूट

- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) केवल 1 | (b) केवल 2 |
| (c) 1 और 2 दोनों | (d) न तो 1 और न ही 2 |

➤ **उत्तर (a)**

व्याख्या 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय के संबंध में कथन (1) असत्य है, क्योंकि इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिक-से-अधिक 6 अन्य न्यायाधीश होते थे।

संघीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा होती थी तथा वे 65 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करते थे।

यद्यपि इससे पूर्व भी इन्हें कदाचार अथवा शारीरिक/मानसिक असमर्थता के आधार पर प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति की सिफारिश पर हटाया जा सकता था।

16. 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडलों की स्थापना के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

- (a) इस अधिनियम द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई।
- (b) द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था वाले प्रांत बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा मद्रास थे।
- (c) द्विसदनीय विधानमंडल में उच्च सदन विधानसभा थी।
- (d) द्विसदनीय विधानमंडल में निम्न सदन राज्य परिषद् थी।

➤ **उत्तर (a)**

व्याख्या 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडलों की स्थापना के संदर्भ में कथन (a) सही है। भारत शासन अधिनियम, 1935 के द्वारा 6 प्रांतों में यथा—बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, बंबई एवं मद्रास में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त 5 प्रांतों में एक सदनीय विधानमंडलों की स्थापना की गई। विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद् तथा निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। विधान परिषद् एवं विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग-अलग प्रांतों में भिन्न-भिन्न थी। विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, किंतु विधान परिषद् में यह व्यवस्था जारी रखी गई।

17. ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति (कैबिनेट मिशन) द्वारा मई, 1946 में प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है?

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

- (a) भारत में एक संघीय शासन की स्थापना।

- (b) किसी भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न पर विधानमंडल का निर्णय उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले उस संप्रदाय के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से होना चाहिए।
- (c) संघ की एक कार्यपालिका तथा विधायिका होनी चाहिए, जिसमें प्रांतों तथा देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- (d) संघीय सरकार का क्षेत्राधिकार वैदेशिक संबंध, प्रतिरक्षा तथा संचार व्यवस्था तक सीमित होना चाहिए।

➤ **उत्तर (b)**

व्याख्या ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मई, 1946 में प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में कथन (b) असत्य है।

ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति (कैबिनेट मिशन) ने भारत के सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से विचार-विमर्श करने के पश्चात् 16 मई, 1946 को एक योजना (दीर्घकालीन समझौते हेतु) प्रस्तुत की गई, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है।

इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न पर विधानमंडल का निर्णय उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले उस संप्रदाय के कुल सदस्यों के बहुमत से होना चाहिए, न कि 2/3 बहुमत से। मंत्रिमंडलीय योजना के प्रस्ताव के अन्य प्रावधान थे—संघीय शासन की व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतीय स्वायत्तता तथा संघीय न्यायालय की स्थापना।

18. निम्न कथन (A) व कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

कथन (A) ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा एक अंतरिम सरकार की स्थापना की परिकल्पना की गई थी।

कारण (R) संविधान की निर्माण विधि में शासन संचालन हेतु अंतरिम सरकार की स्थापना की परिकल्पना की गई थी, जिसमें सभी पद भारतीयों को दिए जाने की व्यवस्था थी। (Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

कूट

- (a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
- (b) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (c) A सही है, किंतु R गलत है।
- (d) A गलत है, किंतु R सही है।

➤ **उत्तर (a)**

व्याख्या कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।

ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति ने 16 जून, 1946 को (अल्पकालिक योजना के अंतर्गत) एक अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए थे। अंतरिम सरकार का कार्य संविधान की निर्माणविधि में शासन को संचालित करना था।

अंतरिम सरकार में सभी पद भारतीयों को दिए जाने का प्रावधान किया गया था और ब्रिटिश सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि अंतरिम सरकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनमें वह सहयोग प्रदान करेगा।

19. ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार अंतरिम सरकार में किनके प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना था?

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. कांग्रेस | 2. मुस्लिम लीग |
| 3. भारतीय ईसाई | 4. सिख |
| 5. पारसी समुदाय | |

NCERT MCQs • संवैधानिक विकास 05

कूट

- (a) 1 और 2 (b) 1, 2 और 3
(c) 1, 2, 3 और 4 (d) ये सभी

➤ उत्तर (d)

व्याख्या ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार अंतरिम सरकार में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय ईसाई, सिख तथा पारसी समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने का प्रावधान था। इस प्रकार दिए गए उपर्युक्त सभी प्रतिनिधि को शामिल किया जाना था।

अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्यों को शामिल किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इन 14 सदस्यों में से 6 सदस्य कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख तथा 1 पारसी समुदाय के प्रतिनिधि थे।

20. माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

1. भारत के विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
2. इस योजना के अंतर्गत विवादग्रस्त चार प्रांतों असम, बंगाल, पंजाब तथा उड़ीसा का विभाजन किए जाने का प्रावधान था।
3. असम के सिलहट क्षेत्र में विभाजन का निर्णय जनमत द्वारा किया जाना था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) 1 और 3
(c) 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

➤ उत्तर (b)

व्याख्या माउंटबेटन योजना के संबंध में कथन (1) और (3) सत्य हैं। ब्रिटिश सरकार ने सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने हेतु लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर-जनरल बनाकर भारत भेजा।

माउंटबेटन 24 मार्च, 1947 को भारत पहुँचा। जहाँ गहन विचार-विमर्श के पश्चात् उसने 3 जून, 1947 को अपने नीति विषयक बयान (भारत विभाजन की योजना) जारी किया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है।

इस योजना में यह प्रावधान था कि असम के सिलहट क्षेत्र में जनमत द्वारा यह निश्चय किया जाएगा कि वह असम में रहेगा अथवा पूर्वी बंगाल में सम्मिलित होना चाहेगा, जो पाकिस्तान का एक अंग होगा।

कथन (2) असत्य है, क्योंकि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत चार प्रांतों में नहीं, बल्कि तीन प्रांतों-असम, बंगाल तथा पंजाब का विभाजन किए जाने का प्रावधान था।

21. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के अंतर्गत कौन-सा प्रावधान शामिल नहीं था?

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

1. भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना।
2. देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल होने की छूट दी गई।
3. जनजातीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बरकरार रखा गया।
4. भारत या पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों को कॉमनवेल्थ से अलग होने की छूट प्राप्त थी।

कूट

- (a) 2 और 3 (b) केवल 3
(c) केवल 4 (d) 3 और 4

➤ उत्तर (b)

व्याख्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 में जनजातीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बरकरार रखे जाने का प्रावधान शामिल नहीं था। इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों से ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया तथा जो भी संधियाँ अथवा समझौते ब्रिटिश सरकार तथा जनजातियों के बीच, अधिनियम लागू होने के दिन विद्यमान थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया।

22. 1949 में अंगीकृत भारतीय संविधान मुख्यतः किस अधिनियम से प्रभावित था?

(Chap 1, Class-XI, Old NCERT)

- (a) 1892 का भारतीय परिषद् अधिनियम
(b) 1935 का भारतीय शासन अधिनियम
(c) 1919 का भारतीय शासन अधिनियम
(d) 1909 का भारतीय परिषद् अधिनियम

➤ उत्तर (b)

व्याख्या 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का माना जाता है। 1935 के अधिनियम द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी। इसके अतिरिक्त केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायालय आदि के प्रावधान इसी अधिनियम के अंतर्गत ही किए गए थे।

संविधान निर्माण की प्रक्रिया

Old NCERT Class VII हमने अपना संविधान कैसे बनाया, New NCERT Class IX संविधान निर्माण,
Old NCERT Class IX & X सभारतीय संविधान और उसकी विशेषताएँ,
New NCERT Class XI संविधान क्यों और कैसे

संविधान का परिचय

1. संविधान के कार्यों के संबंध में दिए गए कथनों में कौन-सा कथन सत्य नहीं है?

(Chap 1, Class-XI, New NCERT)

- समाज में न्यूनतम समन्वय व विश्वास हेतु बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना।
- निर्णय लेने वाली संस्था को सुनिश्चित करना।
- नागरिकों एवं सरकार की सीमाएँ सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ।

उत्तर (d)

व्याख्या संविधान के कार्यों के संबंध में कथन (d) सत्य नहीं है। संविधान उन विनियमों व नियमों का लिखित दस्तावेज होता है, जिसके आधार पर देश के शासन का संचालन होता है। इसके अंतर्गत सरकार के अंगों व जनता के अधिकार, कार्य एवं दायित्वों का वर्णन होता है। इस प्रकार संविधान अनेक कार्य करता है, जिनमें कुछ प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं

- संविधान का पहला कार्य यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए, जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे।
- संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। वह यह भी निर्धारित करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा।
- संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमाएँ भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है, जिससे सरकार कभी उसका उल्लंघन न कर पाए।
- संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है, जिससे कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 1, Class-XI, New NCERT)

- राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग-अलग संविधान में अलग-अलग तरीकों की होती है।

- भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता देता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर (b)

व्याख्या दिए गए कथनों में कथन (2) असत्य है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न-भिन्न अवधारणाएँ होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है।

उदाहरणस्वरूप जर्मनी का निर्माण 'जर्मन नस्ल' के आधार पर हुआ और जर्मनी के संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति भी दी, किंतु दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 1, Class-XI, New NCERT)

- विभिन्न देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं, क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती।
- भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के संविधान विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान के उदाहरण हैं। इन संविधानों को एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात् बनाया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर (c)

व्याख्या दिए गए कथनों में कथन (1) और (2) दोनों सत्य हैं। विश्व के कई देशों में संविधान सफल व प्रभावी नहीं हो पाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनके पास देश के सभी वर्गों, समुदायों आदि को एक साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है।

भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका आदि देशों के संविधान को विश्व का सर्वाधिक सफल संविधान माना जाता है, क्योंकि इन देशों के संविधान का निर्माण

NCERT MCQs • संविधान निर्माण की प्रक्रिया 07

एक व्यापक व सफल राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात् किया गया और इन राष्ट्रीय आंदोलनों में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। इस तरह इन देशों के संविधानों को लोगों का व्यापक समर्थन मिला।

4. निम्न कथन (A) व कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए।

(Chap 1, Class-XI, New NCERT)

कथन (A) संविधान केवल सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम है।

कारण (R) संविधान सरकार को ऐसी शक्तियाँ देता है, जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके।

कूट

- A और R दोनों सही हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
- A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A का स्पष्टीकरण नहीं है।
- A सही है, किंतु R गलत है।
- A गलत है, किंतु R सही है।

➤ **उत्तर (d)**

व्याख्या कथन (A) गलत है, किंतु कारण (R) सही है। संविधान केवल सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, बल्कि संविधान सरकार को ऐसी क्षमता व शक्तियाँ भी प्रदान करता है, जिससे कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इसके अतिरिक्त संविधान एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के निर्माण का कार्य भी करता है।

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 1, Class-XI, New NCERT)

- अधिक कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं।
- यदि संविधान अत्यधिक लचीला है, तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान दे सकता है।
- एक अच्छा संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- केवल 3
- 1 और 2

➤ **उत्तर (b)**

व्याख्या दिए गए कथनों में कथन (2) सत्य नहीं है। संविधान की रूपरेखा बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन का संतुलन हो जिससे वह बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल सके, क्योंकि अधिक कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं और यदि संविधान अत्यधिक लचीला है, तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान नहीं दे सकेगा। अतएव एक अच्छा संविधान वही होता है, जिसमें मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता अथवा योग्यता हो।

6. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा इस बात की धारणा को स्पष्ट करता है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से अधिक है?

(Chap 1, Class-XI, New NCERT)

- संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था।
- संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं अधिक बड़े नेता थे।
- संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इनकी शक्तियाँ तथा उसकी सीमाएँ क्या होंगी।
- संसद, संविधान का संशोधन नहीं कर सकती है।

➤ **उत्तर (c)**

व्याख्या संविधान की प्रामाणिकता संसद से अधिक है, यह इस बात से प्रमाणित होता है कि संविधान द्वारा ही संसद के गठन की प्रक्रिया, उसकी शक्तियाँ तथा सीमाएँ निर्धारित होती हैं।

संविधान ही यह तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार (संसद) द्वारा अपने नागरिकों के लिए बनाए जाने वाले कानूनों की सीमा निर्धारित करना है। संसद, संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती है।

7. निम्न कथन (A) तथा कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए।

(Chap 1, Class-XI, New NCERT) (UPPSC Pre 2015)

कथन (A) भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है।

कारण (R) मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है।

कूट

- A और R दोनों सही हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
- A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- A सही है, किंतु R गलत है।
- A गलत है, किंतु R सही है।

➤ **उत्तर (b)**

व्याख्या कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परंतु कारण (R), कथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

भारतीय संविधान दुनिया का सबसे वृहत्तर (लंबा) संविधान है। यहाँ केंद्र तथा राज्यों का संविधान एक साथ होने के कारण इसकी लंबाई अधिक है।

भारतीय संविधान के कई उपबंध विभिन्न देशों के संवैधानिक मॉडल पर आधारित हैं। 'मौलिक अधिकारों' के उपबंध अमेरिका के संविधान के मॉडल पर आधारित हैं।

8. निम्न कथन (A) तथा कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए।

(Chap 4, Class-IX & X, Old NCERT)

कथन (A) भारतीय संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है, जिसके अनुसार देश की शासन प्रणाली का क्रियान्वयन होता है।

कारण (R) भारतीय संविधान के आधार पर ही देश के किसी कानून का निर्माण किया जाता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता, जो संविधान के अनुकूल नहीं हो।

कूट

- A और R दोनों सही हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
- A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- A सही है, किंतु R गलत है।
- A गलत है, किंतु R सही है।

➤ **उत्तर (a)**

व्याख्या कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।

भारतीय संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है, जिसके आधार पर सरकार के प्रमुख अंगों के कार्यक्षेत्र तथा नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाता है।

कोई भी कानून संविधान के उपबंधों के आधार पर बनाया जाता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है, जो संविधान के उपबंधों के अनुकूल न हो।

NCERT MCQs • संविधान निर्माण की प्रक्रिया 08

संविधान सभा का गठन/संविधान निर्माण

9. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(Chap 1, Class-VII, Old NCERT)

- ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्नों के समाधान हेतु एक तीन सदस्यीय कैबिनेट भारत भेजा।
- कैबिनेट मिशन ने भारत के नए संविधान की रचना हेतु एक संविधान सभा के गठन की सिफारिश की।
- भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के निर्वाचन के लिए जुलाई, 1946 में चुनाव कराए गए।
- उपर्युक्त सभी

उत्तर (d)

व्याख्या दिए गए सभी कथन सत्य हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने मार्च, 1946 में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। इसके लिए ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्नों के समाधान तलाशने के लिए कैबिनेट मिशन के रूप में एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल भारत भेजा।

इसके सदस्यों में लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस (अध्यक्ष), सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व ए. वी. अलेक्जेंडर शामिल थे। 16 मई, 1946 को इस कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। इस मिशन की सिफारिशों के अनुसार संविधान सभा के निर्वाचन के लिए जुलाई, 1946 में चुनाव कराए गए।

10. निम्न कथनों पर विचार कीजिए। (Chap 1, Class-XI, New NCERT)

- संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से किया गया।
- संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत गठित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर (b)

व्याख्या दिए गए कथनों में कथन (2) सत्य है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा न होकर, भारतीय शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत गठित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से कराया गया। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई, जिसे कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था।

11. निम्न कथन (A) व कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए।

(Chap 1, Class-XI, New NCERT)

कथन (A) संविधान सभा के निर्वाचन में सामान्यतः दस लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था।

कारण (R) प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा की सीटें दी गई थीं।

कूट

- A और R दोनों सही हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
- A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- A सही है, किंतु R गलत है।
- A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर (a)

व्याख्या कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।

कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा की सीटें प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान की गई थीं। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दस लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि (या एक सीट) निश्चित किया गया।

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 1, Class-XI, New NCERT) (IAS Pre 2011)

- ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से संविधान सभा के 292 सदस्य चुनने थे।
- देशी रियासतों को संविधान सभा की न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गईं।
- प्रत्येक प्रांत की सीटों को मुस्लिम, सिख और सामान्य तीन समुदायों में बांटा गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- केवल 1
- 1 और 2
- 2 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर (d)

व्याख्या प्रश्न में दिए गए सभी कथन सत्य हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले 11 प्रांतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के प्रांतों से व 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाने थे।

प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य में विभाजित कर दिया गया था और प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते थे।

13. भारतीय संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (Chap 1, Class-VII, Old NCERT) (UPPSC Mains 2011)

- इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई।
- सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर (c)

व्याख्या भारतीय संविधान के बारे में दिए गए दोनों कथन (1) और (2) सत्य हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन हॉल में हुई थी। इस बैठक में सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर, 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

संविधान सभा में अपनी स्थिति को कमजोर देखते हुए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त, 1946 को 'सीधी कार्रवाई दिवस' मनाते हुए, एक अलग संविधान सभा की माँग की और संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया।

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 2, Class-IX, New NCERT)

- संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था।

NCERT MCQs • संविधान निर्माण की प्रक्रिया 09

- संविधान सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म व पेशों के लोगों का अभाव था।
- संविधान सभा में कांग्रेस के कई ऐसे सदस्य थे, जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 3 (d) 1 और 2

➤ उत्तर (b)

व्याख्या दिए गए कथनों में कथन (2) सत्य नहीं है, क्योंकि सामाजिक रूप से संविधान सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, अनुसूचित जाति व जनजाति, कानून के विद्वान और पेशेवर लोग शामिल थे।

संविधान सभा में कांग्रेस को 208 सीटें (199 सदस्य कांग्रेस के और 9 सदस्य कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार) प्राप्त हुई थीं, जबकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें व 8 स्वतंत्र सदस्य थे। इस तरह संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था।

संविधान सभा में कांग्रेस के अंदर कई राजनैतिक समूह और विचार के लोग थे। इसमें कई सदस्य ऐसे थे, जो किसी विशेष मुद्दे पर कांग्रेस के विचार से असहमत होकर उसका विरोध करते थे।

15. निम्न में कौन-से सदस्यों ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया? (Chap 1, Class-VII, Old NCERT)

- फ्रेक एंथनी
- डॉ. एच. पी. मोदी
- सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
- जयपाल सिंह

कूट

- (a) 1 और 4 (b) 2 और 3
(c) 1 और 2 (d) 1 और 3

➤ उत्तर (c)

व्याख्या संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों यथा-एंग्लो-इंडियन और पारसियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः फ्रेक एंथनी और डॉ. एच. पी. मोदी ने किया। संविधान सभा में लगभग सभी समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। अल्लादि कृष्णास्वामी कानूनी विद्वान् थे, जबकि जयपाल सिंह आदिवासी समुदाय से थे।

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 10, Class-XI, New NCERT)

- विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए संविधान सभा की आठ मुख्य कमेटियाँ थीं।
- जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी. आर. अंबेडकर आदि ने इन कमेटियों की अध्यक्षता की।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

➤ उत्तर (c)

व्याख्या दिए गए दोनों कथन (1) और (2) सत्य हैं। संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें आठ मुख्य व बड़ी समितियाँ थीं तथा अन्य छोटी थीं। इन प्रमुख समितियों में जवाहरलाल नेहरू (संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान

समिति), राजेंद्र प्रसाद (प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति), बी. आर. अंबेडकर (प्रारूप समिति) ने अध्यक्षता की थी।

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 2, Class-IX, New NCERT)

- प्रारूप समिति ने प्रत्येक अनुच्छेद पर कई दौर में चर्चाएँ कीं।
 - प्रारूप समिति ने दो हजार से अधिक संशोधनों पर विचार किया।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

➤ उत्तर (c)

व्याख्या दिए गए दोनों कथन (1) और (2) सही हैं।

संविधान सभा का कार्य व्यवस्थित तथा सर्वसम्मति पर आधारित था। सबसे पहले बुनियादी सिद्धांतों पर सर्वसम्मति का प्रयास किया गया। डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने एक 'प्रारूप' तैयार किया। संविधान के इस प्रारूप की धाराओं पर चर्चा की गई। दो हजार से अधिक संशोधनों के बाद इसे प्रभावी रूप दिया गया।

18. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

(Chap 1, Class-VII, Old NCERT)

- (a) 26 नवंबर, 1949 को कुल 284 सदस्यों ने पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे।
(b) भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
(c) वर्ष 1952 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद विधिवत् निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति बने।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

➤ उत्तर (d)

व्याख्या दिए गए सभी कथन (a), (b) और (c) सत्य हैं।

26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। इस दिन संविधान सभा के 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। यद्यपि संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर, 1949 को ही लागू हो गए थे।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी, 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, किंतु वह विधान के अनुसार विधिवत् निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति वर्ष 1952 में बने। इस प्रकार कोई भी कथन असत्य नहीं है।

19. 26 जनवरी, 1950 को गणतंत्र दिवस मनाए जाने का कारण है

(Chap 1, Class-VII, Old NCERT)

- (a) 26 जनवरी, 1929 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था।
(b) 26 जनवरी, 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था।
(c) 26 जनवरी, 1931 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था।
(d) वर्ष 1929 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था।

➤ उत्तर (b)

व्याख्या 26 जनवरी, 1950 के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने का अपना ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि 26 जनवरी, 1930 को (कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, दिसंबर, 1929 में पारित संकल्प के आधार पर) पूर्ण स्वराज दिवस (स्वतंत्रता दिवस) मनाया गया था। तब से वर्ष 1947 तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी की

NCERT MCQs • संविधान निर्माण की प्रक्रिया 10

इसी स्मृति को ताजा रखने के लिए 26 जनवरी, 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया।

20. निम्न कथन किसका है?

(Chap 2, Class-IX, New NCERT)

“26 जनवरी, 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति-एक वोट और ‘हर वोट का समान महत्त्व’ के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढाँचे के कारण ही, ‘एक व्यक्ति-एक वोट’ के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। यदि यह नकारना अधिक लंबे समय तक चला, तो हम अपने राजनैतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे।”

- जवाहरलाल नेहरू
- महात्मा गाँधी
- बी. आर. अंबेडकर
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद

उत्तर (c)

व्याख्या उपर्युक्त कथन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर का है। यह कथन 25 नवंबर, 1946 को संविधान सभा में बी. आर. अंबेडकर के अंतिम भाषण का अंश है, जिसमें उन्होंने भारत के भविष्य की चिंताओं को सामने रखा था।

बी. आर. अंबेडकर (1891-1956) सामाजिक क्रांतिकारी, चिंतक, जातिगत विभाजन और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री थे।

21. निम्नलिखित में से कौन-सा/से युग्म सुमेलित नहीं है/हैं?

(Chap 2, Class-IX, New NCERT) (IAS Pre 2005)

- बी. आर. अंबेडकर — प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद — संविधान सभा के अध्यक्ष
- टी. टी. कृष्णामाचारी — संविधान सभा के उपाध्यक्ष
- के. एम. मुंशी — प्रारूप कमेटी के सदस्य

उत्तर (c)

व्याख्या युग्म (c) सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि टी. टी. कृष्णामाचारी (1899-1974) संविधान सभा के उपाध्यक्ष नहीं बल्कि प्रारूप समिति के

सदस्य थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच. सी. मुखर्जी थे। टी. टी. कृष्णामाचारी तमिलनाडु के उद्यमी और कांग्रेस के नेता थे, जो बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्तमंत्री बने।

22. सूची-I का सूची-II के साथ सही सुमेलन कीजिए।

(Chap 2, Class-IX, New NCERT)

सूची-I (अंतरिम सरकार के मंत्री)	सूची-II (पद)
A. वल्लभभाई पटेल	1. वित्तमंत्री
B. अबुल कलाम आजाद	2. रक्षामंत्री
C. जॉन मथाई	3. सूचना एवं प्रसारण मंत्री
D. बलदेव सिंह	4. शिक्षामंत्री

कूट

	A	B	C	D
(a)	3	1	2	4
(c)	3	1	4	2

उत्तर (b)

व्याख्या सही सुमेलन A-3, B-4, C-1, D-2 है।

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। पटेल ने भारतीय रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में, वे देश के प्रथम उपप्रधानमंत्री बने।

अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षामंत्री थे। आजाद शिक्षाविद्, लेखक, धर्मशास्त्र के ज्ञाता और अरबी के विद्वान थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई।

जॉन मथाई अंतरिम सरकार में वित्तमंत्री थे। इन्होंने मुस्लिम लीग के सदस्य लियाकत अली खान के त्यागपत्र के बाद यह पद संभाला।

बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रक्षामंत्री थे। वह सफल उद्यमी, पंजाब विधानसभा में पृथक् अकाली पार्टी के नेता और संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत थे।

03

भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मुख्य विशेषताएँ

Old NCERT Class VII हमारे आदर्श क्या हैं-प्रस्तावना, Old NCERT Class VII हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएँ, New NCERT Class IX संविधान का निर्माण, Old NCERT Class IX & X भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएँ, New NCERT Class XI संविधान : क्यों और कैसे?, Old NCERT Class XI संविधान का राजनीतिक दर्शन, Old NCERT Class XI भारतीय संविधान : प्रस्तावना, मुख्य विशेषताएँ तथा भारतीय संघ

प्रस्तावना

1. भारतीय संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। (Chap 3, Class-XI, Old NCERT)

1. भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी, 1947 को पारित किया।
2. 'उद्देश्य प्रस्ताव' 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में दिया गया भाषण था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर (c)

व्याख्या भारतीय संविधान सभा के 'उद्देश्य प्रस्ताव' के संदर्भ में कथन (1) और (2) दोनों सत्य हैं। भारतीय संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी, 1947 को पारित किया था। उल्लेखनीय है कि इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर, 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत एक पूर्णतया स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुतासंपन्न गणराज्य होगा। वह अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा तथा भारतीय संघ और उसके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगी।

2. निम्न कथन (A) व कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए।

(Chap 1, Class-XI, New NCERT)

कथन (A) राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया, उसका सर्वोत्तम सारांश हमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1946 में प्रस्तुत 'उद्देश्य-प्रस्ताव' में मिलता है।

कारण (R) उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था और सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था।

कूट

- (a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(b) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(c) A सही है, किंतु R गलत है।
(d) A गलत है, किंतु R सही है।

उत्तर (a)

व्याख्या कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।

भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर, 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। इस प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढाँचे एवं दर्शन को प्रतिबिंबित किया गया था।

'उद्देश्य प्रस्ताव' में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं तथा मूल्यों को समाहित किया गया था।

संविधान के मौलिक प्रावधान वस्तुतः उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित तथा उनका सारांश हैं। इस प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया है।

3. संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्न शब्दों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। (Chap 4, Class-IX & X, Old NCERT)

(BPS Pre 2008)

1. समाजवादी
2. प्रजातांत्रिक
3. सार्वभौमिक
4. पंथनिरपेक्ष

NCERT MCQs • भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मुख्य विशेषताएँ 12

कूट

- (a) 1, 2, 3, 4 (b) 1, 2, 3, 4
(c) 3, 1, 4, 2 (d) 2, 1, 3, 4

उत्तर (c)

व्याख्या संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही व्यवस्थित क्रम—संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न (सार्वभौमिक), समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक (प्रजातंत्रात्मक), गणराज्य है, जोकि उद्देशिका अथवा प्रस्तावना में निहित है।

4. संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 2, Class-IX, New NCERT)

1. भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों की झलक प्रस्तावना में मिलती है।
2. 'प्रस्तावना' को 'भारतीय संविधान की आत्मा' कहा गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर (c)

व्याख्या संविधान सभा की 'प्रस्तावना' के संबंध में कथन (1) और (2) दोनों सत्य हैं। संविधान की प्रस्तावना संविधान के मुख्य आदर्शों, आकांक्षाओं एवं बुनियादी मूल्यों का उल्लेख करती है। इसमें लोकतंत्र, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, न्याय आदि के दर्शन अंतर्निहित हैं।

यह संविधान का प्रेरणास्रोत है। अतः जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध अथवा अस्पष्ट है, वहाँ प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है।

प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अतः प्रस्तावना को 'संविधान की मूल आत्मा' कहा जाता है।

5. प्रस्तावना के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(Chap 2, Class-VII, Old NCERT)

- (a) लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं।
- (b) प्रस्तावना में वर्णित शब्द शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं।
- (c) प्रस्तावना में उल्लिखित सिद्धांतों पर नागरिकों की पूर्ण आस्था नहीं है।
- (d) इसके आधार पर सामाजिक-आर्थिक विषमताओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

उत्तर (c)

व्याख्या प्रस्तावना के संदर्भ में दिए गए कथनों में कथन (c) असत्य है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों, मूल्यों एवं दर्शन पर भारत के समस्त नागरिकों की पूर्ण आस्था है। प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता को प्राप्त करने और उन सभी में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने तथा बंधुता बढ़ाने के दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया गया है।

6. निम्नलिखित में से किन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 'प्रस्तावना' में जोड़ा गया?

(Chap 3, Class-XI, Old NCERT) (BPS Pre 2016)

1. समाजवादी
2. ग्राम स्वराज
3. पंथनिरपेक्षता
4. संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न

कूट

- (a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 3
(c) 1, 2 और 4 (d) 2, 3 और 4

उत्तर (b)

व्याख्या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा पहली बार 'प्रस्तावना' में संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' तथा 'अखंडता' शब्द को जोड़ा गया।

7. प्रस्तावना में वर्णित 'संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न' शब्द से अभिप्राय है

(Chap 3, Class-XI, Old NCERT)

- (a) ऐसी व्यवस्था, जहाँ भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो।
- (b) ऐसी व्यवस्था, जहाँ भारतवर्ष आंतरिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र, किंतु बाह्य रूप से प्रभावित हो।
- (c) ऐसी व्यवस्था, जहाँ भारतवर्ष आंतरिक तथा बाह्य सत्ता से प्रभावित हो।
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर (a)

व्याख्या संविधान की प्रस्तावना में भारत को 'संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न' राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया है। इससे आशय यह है कि भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में किसी विदेशी शक्ति अथवा सत्ता के अधीन नहीं है। वह अपनी आंतरिक एवं बाह्य विदेश नीति निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता एवं संधि करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है।

8. प्रस्तावना में वर्णित पंथनिरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

(Chap 4, Class-IX & X, Old NCERT)

1. राज्य का अपना कोई निजी धर्म नहीं है।
2. नागरिकों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है।
3. राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित कर सकता है।
4. धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है।

कूट

- (a) 1, 2 और 3 (b) 1, 2 और 4
(c) 2, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर (b)

व्याख्या प्रस्तावना में वर्णित पंथनिरपेक्षता के संबंध में कथन (1), (2) और (4) सत्य हैं। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा अर्थात् राज्य किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ रूप से समान संरक्षण प्रदान करता है।

राज्य में धर्म को एक वैयक्तिक विषय के रूप में माना जाता है, जिसके अनुसार नागरिकों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है।

कथन (3) असत्य है, क्योंकि राज्य किसी धर्म-विशेष को प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्रकार यहाँ सभी धर्मों का समान महत्त्व है।

9. भारत के संविधान की 'उद्देशिका'

(Chap 3, Class-XI, Old NCERT) (IAS Pre 2020)

- (a) संविधान का भाग है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती।
- (b) संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती।
- (c) संविधान का भाग है और ऐसा ही विधिक प्रभाव रखती है, जैसा कि उसका कोई अन्य भाग।
- (d) संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है।

उत्तर (d)

NCERT MCQs • भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मुख्य विशेषताएँ 13

व्याख्या उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसे वैधानिक रूप से न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता अर्थात् अन्य भागों से स्वतंत्र होकर भी इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। प्रस्तावना (उद्देशिका) का लक्ष्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है, जहाँ जनता संप्रभु हो, शासन निर्वाचित हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। शासन की सत्ता मौलिक अधिकारों से सीमित हो तथा जनता को अपने विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो।

10. प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। इस संदर्भ में कौन-सा कथन इसकी पुष्टि नहीं करता है?

(Chap 2, Class-VII, Old NCERT)

- राज्य का मुखिया निर्वाचित राष्ट्रपति होता है।
- राज्य का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है।
- राज्य के मुखिया की नियुक्ति वंशानुगत होती है।
- गणराज्य के सभी नागरिक समान होते हैं।

उत्तर (c)

व्याख्या प्रस्तावना में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। इस संदर्भ में कथन (c) इसकी पुष्टि नहीं करता है। भारत के गणराज्य होने का तात्पर्य यह है कि भारत में राज्य का मुखिया (राष्ट्राध्यक्ष) निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। राजतंत्र अथवा राजशाही में राज्य का प्रमुख वंशानुगत आधार पर नियुक्त होता है। भारत का राष्ट्रपति पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है।

11. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है?

(Chap 3, Class-XI, Old NCERT)

- विचार की स्वतंत्रता
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- उपासना की स्वतंत्रता
- धर्म की स्वतंत्रता
- विश्वास की स्वतंत्रता

कूट

- 1, 2 और 4
- 1, 2 और 5
- 1, 2, 3 और 4
- 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर (d)

व्याख्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पाँच प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ये स्वतंत्रता हैं

- विचार की स्वतंत्रता
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- विश्वास की स्वतंत्रता
- धर्म की स्वतंत्रता
- उपासना की स्वतंत्रता

उल्लेखनीय है कि प्रस्तावना के अनुसार उक्त स्वतंत्रताओं को सभी नागरिकों को प्राप्त कराने के लिए भारतीय संविधान दृढ़ संकल्पित है। इस प्रकार प्रस्तावना में उपर्युक्त सभी प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है।

12. लोकतंत्र से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से है, जहाँ सरकार

(Chap 3, Class-XI, Old NCERT)

- जनता द्वारा निर्वाचित होती है।
- अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।
- एक निश्चित अंतराल के पश्चात् निर्वाचित होती है।
- जनता को स्वतंत्रतापूर्वक तथा न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार प्रदान करती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- 1 और 2
- 1, 2 और 3
- 1, 3 और 4
- 1, 2, 3 और 4

उत्तर (c)

व्याख्या लोकतंत्र से अभिप्राय के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कथन (1), (3) और (4) सही हैं। लोकतंत्र से तात्पर्य लोगों का तंत्र अर्थात् जनता का शासन है। इस प्रणाली में सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है। इसके अंतर्गत एक निश्चित समय पर (भारत के संदर्भ में 5 वर्षों के लिए) चुनाव संपन्न होते हैं, जिसमें जनता को स्वतंत्रतापूर्वक तथा न्यायपूर्ण तरीके से मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इससे आशय यह भी है कि इस प्रणाली में विधि का शासन होता है।

कथन (2) सही नहीं है, क्योंकि सरकार अपने कार्यों एवं नीतियों के लिए जनता के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होती है।

13. भारतीय संविधान की 'उद्देशिका' के संबंध में निम्न कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

(Chap 3, Class-XI, Old NCERT) (UPPSC Pre 2009)

- जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत 'ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव' अंततोगत्वा उद्देशिका बना।
- इसकी प्रकृति न्याय योग्य (Justiciable) नहीं है।
- इसका संशोधन नहीं किया जा सकता।
- संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता।

कूट

- 1 और 2
- 1, 2 और 4
- 1, 2 और 3
- 2, 3 और 4

उत्तर (b)

व्याख्या भारतीय संविधान की 'उद्देशिका' के संबंध में कथन (1), (2) और (4) सही हैं। 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 'ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव' रखा, जो अंततः 'प्रस्तावना' (उद्देशिका) के रूप में सामने आया। उद्देशिका की प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं है। इसके वर्णित उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए व्यक्ति न्यायालय में दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह संविधान के किसी प्रावधान को रद्द नहीं कर सकता।

कथन (3) सही नहीं है, क्योंकि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है।

14. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है?

(Chap 3, Class-XI, Old NCERT)

- सामाजिक न्याय
- आर्थिक न्याय
- राजनीतिक न्याय
- धार्मिक न्याय

उत्तर (d)

व्याख्या प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख है

- सामाजिक न्याय का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है, जहाँ जाति, मत, रंग, लिंग, जन्मस्थान, धर्म या भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो अर्थात् समाज में किसी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार प्राप्त न हो।
- राजनैतिक न्याय का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है, जहाँ सभी नागरिकों को समान रूप से मत देने, चुनाव लड़ने तथा सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार हो।
- आर्थिक न्याय का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है, जहाँ आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत संपदा, आय तथा संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है।

NCERT MCQs • भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मुख्य विशेषताएँ 14

15. निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए।

(Chap 4, Class-IX & X, Old NCERT)

- (a) प्रस्तावना संविधान की व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- (b) प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किए जाने पर इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- (c) प्रस्तावना सरकार की शासन संचालन की दिशा को इंगित करती है।
- (d) उपर्युक्त सभी

➤ उत्तर (d)

व्याख्या प्रश्न में दिए गए सभी कथन सही हैं। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ भी संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहाँ प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है।

प्रस्तावना/उद्देशिका संविधान का एक भाग या अंश है, किंतु प्रस्तावना न्याय या वाद योग्य नहीं है अर्थात् यदि प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किए जाते हैं तो कोई व्यक्ति इस आधार पर उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता।

यद्यपि इसके बावजूद ये शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं, क्योंकि यह उस दिशा को इंगित करती है जिस दिशा में सरकार को शासन चलाना चाहिए।

16. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है?

(Chap 3, Class-IX & X, Old NCERT) (IAS Pre 2017)

- (a) विचार की स्वतंत्रता
- (b) विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता
- (c) विश्वास की स्वतंत्रता
- (d) आर्थिक स्वतंत्रता

➤ उत्तर (d)

व्याख्या प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात अवश्य की गई है तथा इसे सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका) में विचार करने, विचार प्रकट करने (अभिव्यक्ति) की स्वतंत्रता, विश्वास तथा धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है।

संविधान की विशेषताएँ

17. भारतीय संविधान में समाहित किन विशेषताओं के कारण यह एक 'अनूठा संविधान' बन जाता है? (Chap 3, Class-VII, Old NCERT)

1. लोकतंत्र
2. संघ
3. मूल अधिकार
4. नीति-निदेशक तत्त्व

कूट

- (a) 1 और 3
- (b) 1, 3 और 4
- (c) 1, 2 और 3
- (d) ये सभी

➤ उत्तर (d)

व्याख्या प्रश्न में दी गयी सभी विशेषताओं के कारण भारत का संविधान एक 'अनूठा संविधान' बन जाता है। उसकी कई विशेषताएँ हैं, जो विश्व के अन्य संविधानों से अलग, उसकी पहचान बनाती हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में लोकतंत्र, संघीय व्यवस्था, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति-निदेशक तत्त्व आदि शामिल हैं। इस प्रकार उक्त वर्णित सभी विशेषताएँ भारतीय संविधान की हैं।

18. भारतीय संविधान की कौन-सी विशेषताएँ अद्वितीय हैं?

(Chap 3, Class-XI, Old NCERT)

1. भारतीय जनता द्वारा निर्मित
2. विभिन्न संविधानों का प्रभाव
3. गणराज्य
4. जनता की संप्रभुता
5. विस्तृत संविधान

कूट

- (a) 1, 2 और 5
- (b) 3, 4 और 5
- (c) 1, 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

➤ उत्तर (d)

व्याख्या प्रश्न में दी गयी भारतीय संविधान की सभी विशेषताएँ अद्वितीय हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ दो प्रकार की हैं- अद्वितीय एवं अन्य विशेषताएँ। कुछ विशेषताएँ अद्वितीय हैं जो भारत के किसी पूर्व संविधान में नहीं पाई जाती हैं। भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं

- भारतीय जनता के द्वारा निर्मित
- विभिन्न संविधानों का प्रभाव
- गणराज्य
- जनता की संप्रभुता
- पंथनिरपेक्ष राज्य
- मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य
- राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व
- न्यायिक समीक्षा
- सार्वभौम वयस्क मताधिकार
- नम्य एवं अनम्य (कठोर और लचीला) का मिश्रण।

विस्तृत संविधान का होना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

19. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं है?

(Chap 1, Class-XI, New NCERT)

1. सरकार का संसदीय स्वरूप
2. अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत
3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता
4. कानून निर्माण की विधि
5. कानून के शासन का विचार

कूट

- (a) 2 और 4
- (b) 1, 3 और 5
- (c) 2 और 3
- (d) 2, 3 और 4

➤ उत्तर (c)

व्याख्या अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं हैं। इनमें अवशिष्ट शक्तियाँ, कनाडा के संविधान व न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। जबकि ब्रिटिश संविधान से लिए गए कुछ प्रमुख प्रावधान निम्न हैं

- सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय
- सरकार का संसदीय स्वरूप
- कानून का शासन
- कानून निर्माण की विधि
- द्विसदनीय व्यवस्था
- एकल नागरिकता

NCERT MCQs • भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मुख्य विशेषताएँ 15

20. सूची-I को सूची-II के साथ सही सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए।

(Chap 1, Class-XI, New NCERT) (IAS Pre 2003)

सूची-I (भारतीय संविधान के मद)	सूची-II (जिस देश से अपनाया गया)
A. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत	1. ऑस्ट्रेलिया
B. मूल अधिकार	2. कनाडा
C. संघ-राज्य संबंधों की समवर्ती सूची	3. आयरलैंड
D. भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है	4. यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)
	5. संयुक्त राज्य अमेरिका

कूट

A	B	C	D	A	B	C	D
(a) 5	4	1	2	(b) 3	5	2	1
(c) 5	4	2	1	(d) 3	5	1	2

उत्तर (d)

व्याख्या सही सुमेलन A-3, B-5, C-1, D-2 है।

भारतीय संविधान में वर्णित 'राज्य की नीति के निर्देशक तत्व' आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।

मूल अधिकारों का उपबंध अमेरिका के संविधान से प्रभावित है।

संघ-राज्य संबंधों की समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।

संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होने की शक्ति कनाडा के संविधान से प्रेरित है।

21. भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है?

(Chap 3, Class-XI, Old NCERT)

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| (a) अमेरिकी संविधान | (b) ब्रिटिश संविधान |
| (c) आयरिश संविधान | (d) भारतीय शासन अधिनियम, 1935 |

उत्तर (d)

व्याख्या भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम, 1935 का है। इस अधिनियम से लगभग 250 उपबंधों को संविधान में शामिल किया गया है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक प्रावधान आदि इससे लिए गए हैं। इस तरह संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान हैं अथवा उससे मिलते-जुलते हैं।

22. भारत में नागरिकों के 'संप्रभु' होने अथवा देश की जनता की संप्रभुता से आशय है

(Chap 3, Class-XI, Old NCERT)

- (a) भारतीय जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त है।
- (b) भारतीय जनता को वोट करने का अधिकार प्राप्त है।
- (c) देश की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में अंतर्निहित है।
- (d) भारतीय जनता को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त है।

उत्तर (c)

व्याख्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'संप्रभु अथवा संप्रभुत्व संपन्न' शब्द आया है, जो बताता है कि देश की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में अंतर्निहित है। इससे पूर्व के संवैधानिक प्रावधानों में यह सत्ता ब्रिटिश संसद में सन्निहित थी। संप्रभुता का अंतर्निहित भाव यह है कि भारतीय जनता किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है।

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 3, Class-XI, Old NCERT)

1. राज्य के नीति-निर्देशक तत्व संविधान की एक प्रमुख विशेषता है।
2. यह 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में उल्लेखित निर्देश पत्र के बिल्कुल समान है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर (a)

व्याख्या दिए गए कथनों में कथन (1) सत्य है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय संविधान में 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्व' का उपबंध आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं है।

कथन (2) असत्य है, क्योंकि नीति-निर्देशक तत्व यद्यपि भारतीय शासन अधिनियम, 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र (Instrument of Instruction) के समान है जोकि ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर-जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए जाते थे, किंतु इनमें अंतर यह है कि निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं।

24. भारतीय संविधान की विशेषता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 3, Class-XI, Old NCERT)

1. संविधान संघीय तथा राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों तथा संघीय और राज्यों की कार्यपालिकाओं के क्रिया-कलापों की न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था करता है।
2. संविधान भारत के नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है।
3. संविधान हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
4. संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को जिसने 20 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसे प्रत्येक स्तर पर सरकार के निर्वाचन में भागीदारी का अधिकार प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) 2 और 3
- (c) 2 और 4
- (d) 3 और 4

उत्तर (c)

व्याख्या भारतीय संविधान की विशेषता के संबंध में कथन (2) और (4) सत्य नहीं हैं, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य हेतु उसकी संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है।

संघात्मक संविधान द्वारा सामान्यतः दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है; जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है—एक संघ की नागरिकता तथा दूसरा राज्य की नागरिकता। संविधान द्वारा देश में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसे मतदान करने तथा केंद्र, राज्य और स्थानीय सभी स्तरों पर सरकार के निर्वाचन में भागीदारी का अधिकार प्राप्त है।

NCERT MCQs • भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मुख्य विशेषताएँ 16

25. निम्न में से कौन-सा कथन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता 'संसदीय व्यवस्था' को सही निरूपित नहीं करता है?

(Chap 4, Class-IX & X, Old NCERT)

- (a) संसदात्मक व्यवस्था में संसद की प्रधानता रहती है।
- (b) भारत में संसदात्मक सरकार की व्यवस्था है।
- (c) इसमें शासन का संचालन वस्तुतः मंत्रिपरिषद् द्वारा किया जाता है।
- (d) मंत्रिपरिषद् विधायिका के प्रति अनुत्तरदायी होती है।

➤ उत्तर (d)

व्याख्या भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता 'संसदीय व्यवस्था' को कथन (d) सही निरूपित नहीं करता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद् विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

शासन की संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है।

भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। इस व्यवस्था में संसद की प्रधानता रहती है तथा यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है।

इस प्रणाली में यद्यपि कार्यपालिका का नाममात्र प्रमुख केंद्र एवं राज्यों में क्रमशः राष्ट्रपति व राज्यपाल होता है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर शासन चलाया जाता है। तथापि इसकी वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित होती है, जिसका प्रधान केंद्र एवं राज्यों में क्रमशः प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री होता है।

26. निम्न कथन (A) व कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(Chap 3, Class-XI, Old NCERT)

कथन (A) भारतीय संविधान सुनमनीयता (Flexibility) तथा दुष्मनीयता (Rigidity) का अनुपम मिश्रण है।

कारण (R) किसी राज्य के नाम अथवा सीमा में परिवर्तन संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाता है।

कूट

- (a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
- (b) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (c) A सही है, किंतु R गलत है।
- (d) A गलत है, किंतु R सही है।

➤ उत्तर (b)

व्याख्या कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परंतु कारण (R), कथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई है वह नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। जैसे संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने हेतु विशेष बहुमत (संसद के दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन की सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत एवं उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा कुल सदस्यों में से आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन से) की आवश्यकता होती है। किसी राज्य के नाम अथवा सीमा में परिवर्तन करने हेतु संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे संशोधन (राज्य के नाम अथवा सीमा में परिवर्तन) को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है।

27. भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 3, Class-XI, Old NCERT)

1. भारत में दोहरी नागरिकता की प्रथा नहीं है।

2. नागरिकों को कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं, जो विदेशी नागरिकों को भारत में प्राप्त नहीं हैं।
 3. प्रत्येक भारतीय नागरिक को निश्चित अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त हैं।
 4. भारतीय नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मतदाता भी है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?**
- (a) 1, 2 और 3
 - (b) 2, 3 और 4
 - (c) 1, 3 और 4
 - (d) ये सभी

➤ उत्तर (d)

व्याख्या भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सत्य हैं। भारतीय संविधान में 'नागरिकता' एक विशिष्टता है। भारत में एकल नागरिकता की पद्धति को अपनाया गया है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं, जो विदेशी नागरिकों को नहीं हैं। प्रत्येक भारतीय को निश्चित अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त हैं।

भारतीय नागरिक 'लोकतंत्र' के लिए एक मतदाता भी है और उसे मत देने का अधिकार है।

28. संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 3, Class-VII, Old NCERT)

1. संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है।
 2. इसमें सरकार की दोहरी (संघ सरकार और राज्य सरकार) पद्धति पाई जाती है।
 3. इस प्रणाली में राज्य सरकार संघ सरकार से शक्ति प्राप्त करती है।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?**
- (a) 1 और 2
 - (b) 1 और 3
 - (c) 2 और 3
 - (d) 1, 2 और 3

➤ उत्तर (a)

व्याख्या भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था के संबंध में कथन (1) और (2) सत्य हैं। भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात् इंडिया राज्यों का संघ (Union of States) होगा। संघीय व्यवस्था में सरकार के दो स्तर होते हैं—केंद्र अथवा संघ सरकार तथा राज्यों में राज्य सरकार।

कथन (3) असत्य है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपने अधिकार, दायित्व एवं कार्य आदि की शक्ति संविधान से प्राप्त होती है। उदाहरणस्वरूप, भारत में संघ सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बँटवारा संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत तीन सूचियों संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से स्पष्ट रूप से किया गया है।

29. संविधान के 'उदारवाद' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 10, Class-XI, New NCERT)

1. भारतीय संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल केंद्रीय विधायिका में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
3. संविधान के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) 2 और 3
- (b) 1 और 2
- (c) 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

➤ उत्तर (c)

NCERT MCQs • भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मुख्य विशेषताएँ 17

व्याख्या संविधान के 'उदारवाद' के संदर्भ में कथन (1) और (3) सही हैं। भारतीय संविधान का उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद (Classical Liberalism) से अलग है। शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को महत्त्व देता है, जबकि भारत का संविधान सामाजिक न्याय के साथ जुड़ा है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।

इस संदर्भ में अनुसूचित जाति व जनजाति अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत सरकारी नौकरी के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

कथन (2) सही नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है।

30. निम्न कथन (A) व कारण (R) को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

कथन (A) संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आँच लाए बिना सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है।

कारण (R) जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता से प्रकट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में बहुत पीछे है। (Chap 10, Class-XI, New NCERT)

कूट

- (a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
- (b) A और R दोनों सही हैं, परंतु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (c) A सही है, किंतु R गलत है।
- (d) A गलत है, किंतु R सही है।

➤ **उत्तर (c)**

व्याख्या कथन (A) सही है, किंतु कारण (R) गलत है।

भारतीय संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर संकट लाए बिना सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। इस संदर्भ में समाज के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति हेतु इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संविधान के विशेष उपाय द्वारा विधायिका एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

इस तरह जाति आधारित सकारात्मक कार्य-योजना के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता से स्पष्ट होता है कि भारत दूसरे राष्ट्रों की तुलना में आगे है। उदाहरणस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्य-योजना वर्ष 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन के पश्चात् प्रारंभ हुई, जबकि भारतीय संविधान ने इसे लगभग दो दशक पहले ही अपना लिया था।

31. उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में निम्नलिखित में से किसका संविधान की मूल संरचना के रूप में उल्लेख किया गया है?

1. संविधान की पंथनिरपेक्ष प्रकृति (Chap 4, Class-XI, Old NCERT)
2. संविधान की संघीय प्रकृति
3. संविधान की सर्वोच्चता
4. राज्य का गणतांत्रिक और शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप
5. विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण कूट

- (a) 2, 3 और 4
- (b) 1, 2 और 3
- (c) 2, 3, 4 और 5
- (d) उपर्युक्त सभी

➤ **उत्तर (d)**

व्याख्या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में प्रश्न में दिए गए सभी विकल्पों का संविधान की मूल संरचना के रूप में उल्लेख किया गया है।

केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया, किंतु न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि संविधान की मूल संरचना से उसका अभिप्राय क्या है। यद्यपि संविधान की मूल संरचना के जिन दृष्टांतों का उल्लेख उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में किया गया है, वे निम्नानुसार हैं

- संविधान की सर्वोच्चता
- संविधान की पंथनिरपेक्ष प्रकृति
- राज्य का गणतांत्रिक और शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप
- विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण
- संविधान की संघीय प्रकृति
- मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत
- न्यायिक समीक्षा

04

संघीय क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन

New NCERT Class X संघवाद, Old NCERT Class X राज्यों में हमारी सरकार,
New NCERT Class XI संघवाद, New NCERT Class XII क्षेत्रीय आकांक्षाएँ,
New NCERT Class XII राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ,
Old NCERT Class XII क्षेत्रीय असंतुलन : क्षेत्रवाद, भाषावाद, पृथक्तावाद

1. भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, राज्यों का

(Chap 7, Class-XI, New NCERT) (UPPSC Pre 2008)

- (a) फेडरेशन (b) समूह
(c) यूनियन (d) कंफेडरेशन

उत्तर (c)

व्याख्या भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत 'राज्यों का संघ' (यूनियन) है। संविधान के भाग-1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। राज्यों का यूनियन या संघ मुख्यतः दो बातों को स्पष्ट करता है—पहला, देश का नाम और दूसरा शासन पद्धति का प्रकार।

भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित है। 'संघ' (यूनियन) भारत की संघीय व्यवस्था को श्रेष्ठ रूप में परिभाषित करता है।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

- भारतीय संघ में अधिकांश रियासतों का विलय 15 अगस्त, 1947 से पूर्व ही कर लिया गया था।
- रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित कराने में सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। (Chap 1, Class-XII, New NCERT)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर (c)

व्याख्या दिए गए कथन (1) और (2) दोनों कथन सत्य हैं।

भारतीय संघ में अधिकांश रियासतें (रजवाड़े) जिनकी सीमाएँ स्वतंत्र भारत की नई सीमाओं से मिलती थीं, का विलय शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा 15 अगस्त, 1947 से पूर्व ही कर लिया गया था। अधिकतर रियासतों (रजवाड़ों) के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय हेतु एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसे 'इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन' कहा जाता है।

रियासतों के एकीकरण में या रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय कराने में सरदार वल्लभभाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 15 अगस्त, 1947 तक 136 रियासतों ने भारत में विलय के लिए 'विलय-पत्र' पर हस्ताक्षर किए थे।

3. हैदराबाद रियासत के संदर्भ में कौन-सा कथन असत्य है?

(Chap 1, Class-XII, New NCERT)

- (a) इसका कुछ हिस्सा आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और शेष हिस्सा आंध्र प्रदेश में है।
(b) तेलंगाना क्षेत्र के किसान निजाम के दमनकारी शासन से दुःखी थे।
(c) निजाम के शासन में सबसे अधिक अत्याचार का शिकार महिलाएँ हुई थीं।
(d) हैदराबाद का शासक भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय करने को तैयार था।

उत्तर (d)

व्याख्या हैदराबाद रियासत के संदर्भ में कथन (d) असत्य है, क्योंकि हैदराबाद का शासक जिसे 'निजाम' कहा जाता था, हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में करने के पक्ष में नहीं था। वह यह चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए।

हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया। 13 सितंबर, 1948 को भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन पोलो' के अंतर्गत कार्रवाई की, जिसके बाद अंततः निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में हो गया।

NCERT MCQs • संघीय क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन 19

4. हैदराबाद रियासत में 'रजाकार' किससे संबंधित था?

(Chap 1, Class-XII, New NCERT)

- (a) व्यापारी वर्ग
- (b) अर्द्ध-सैनिक बल
- (c) प्रशासक वर्ग
- (d) कृषक वर्ग

➤ उत्तर (b)

व्याख्या हैदराबाद रियासत में 'रजाकार' अर्द्ध-सैनिक बल के सदस्यों को कहा जाता था। इनकी संख्या लगभग 20 हजार थी। वर्ष 1947-48 में हैदराबाद रियासत में हुए आंदोलन को दबाने के लिए निजाम ने 'रजाकारों' की सहायता ली। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, जिन्होंने विशेष रूप से गैर-मुसलमानों को अपना निशाना बनाया था।

5. जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय-पत्र पर कब हस्ताक्षर किए?

(Chap 8, Class-XII, New NCERT)

- (a) अक्टूबर, 1947
- (b) अक्टूबर, 1948
- (c) दिसंबर, 1947
- (d) दिसंबर, 1948

➤ उत्तर (a)

व्याख्या जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ 26 अक्टूबर, 1947 को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1947 से पूर्व जम्मू-कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, बल्कि अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। अक्टूबर, 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबिलाई घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया, जिसके परिणामस्वरूप हरि सिंह को भारतीय सैनिकों की सहायता लेनी पड़ी। अंततः महाराजा हरि सिंह को भारत सरकार के साथ विलय-प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े।

6. रियासतों/रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के संबंध में निम्नलिखित में कौन-सा कथन असत्य है?

(Chap 1, Class-XII, New NCERT)

- (a) जूनागढ़, हैदराबाद तथा कश्मीर का विलय करने में कठिनाई उत्पन्न हुई।
- (b) हैदराबाद की रियासत को जनमत संग्रह द्वारा भारत में समाहित किया गया।
- (c) भोपाल का विलय भारत में सबसे अंत में हुआ था।
- (d) मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए 'विलय-पत्र' पर हस्ताक्षर किए थे।

➤ उत्तर (b)

व्याख्या रियासतों/रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के संबंध में कथन (b) असत्य है, क्योंकि हैदराबाद की रियासत को जनमत संग्रह द्वारा भारत में समाहित नहीं किया गया था, बल्कि एक सैन्य कार्रवाई द्वारा निजाम को विलय करने के लिए विवश किया गया।

जूनागढ़ में फरवरी, 1948 को जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें सर्वसम्मति से भारत के साथ इस रियासत के विलय को मंजूरी दी गई।

भोपाल रियासत ने सबसे अंत में 1 जून, 1949 को भारत में विलय के लिए सहमति देते हुए विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए।

मणिपुर के शासक ने आंतरिक स्वायत्तता को प्रभावी बनाए रखने के लिए विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए।

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 1, Class-XII, New NCERT)

1. वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया था।
2. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय नेताओं ने सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के कारण राज्यों का भाषाई आधार पर गठन करने से इंकार कर दिया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2
- (d) न तो 1 और न ही 2

➤ उत्तर (c)

व्याख्या दिए गए दोनों कथन (1) और (2) सत्य हैं। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के पश्चात् यह मान लिया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा। इस अधिवेशन में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस-समितियों की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थितियों के बदलने से भाषाई आधार पर राज्यों का गठन एक अव्यवस्था और देश में पुनः विभाजन की स्थिति को दर्शा रहा था। साथ-ही-साथ राष्ट्रीय नेताओं को यह भी लग रहा था कि यदि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ, तो अन्य सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों मुख्य मुद्दा न रहकर एक विकल्प मात्र रह जाएंगी। अतः इन नेताओं ने भाषायी आधार पर राज्यों के गठन से इंकार कर दिया था।

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 1, Class-XII, New NCERT)

1. संविधान में 'राज्यों का संघ' शब्द भारतीय राज्यों को पृथक् होने का अधिकार नहीं देते।
2. ए के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरियता दी।
3. पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) 1 और 2
- (c) 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

➤ उत्तर (d)

व्याख्या प्रश्न में दिए गए सभी कथन सत्य हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'यूनियन ऑफ स्टेट्स' अर्थात् 'राज्यों का संघ' बताया गया है। राज्य, संघ की ऐसी इकाई हैं जिन्हें पृथक् होने का अधिकार नहीं है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया के लिए ए के धर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बदले प्रशासनिक आधार को महत्त्व दिया। धर आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में चर्चा की गई, जहाँ कार्य समिति में शामिल जवाहरलाल नेहरू तथा वल्लभभाई पटेल ने भाषाई पुनर्गठन का विरोध किया।

9. भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(Chap 14, Class-XII, New NCERT)

(UPPSC Mains 2009)

1. भाषाई आधार पर भारत में गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था।

NCERT MCQs • संघीय क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन 20

2. भाषाई आधार पर पृथक् आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आंदोलन करने वाले कांग्रेसी नेता पी. श्रीरामुलु का निधन लंबी भूख हड़ताल के कारण हो गया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

➤ उत्तर (c)

व्याख्या भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में दोनों कथन (1) और (2) सत्य हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 1953 में मद्रास में तेलुगू भाषी क्षेत्रों को पृथक् कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर पृथक् आंध्र प्रदेश की स्थापना के लिए एक लंबा विरोध आंदोलन भी हुआ था, जिसके अंतर्गत 50 दिनों की भूख-हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोर्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया था।

10. राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (Chap 1, Class-XII, New NCERT) (UPPSC Pre 1990)

1. इस आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था।
2. इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामले पर विचार करना था।
3. इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1956 में प्रस्तुत की थी।
4. इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

- (a) केवल 2 (b) केवल 3
(c) केवल 4 (d) इनमें से कोई नहीं

➤ उत्तर (b)

व्याख्या राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में कथन (3) सही नहीं है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की थी।

राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली की अध्यक्षता में वर्ष 1953 में गठित किया गया था। यह एक तीन सदस्यीय आयोग था, जिसके अन्य दो सदस्यों में के. एम. पणिकर तथा एच. एन. कुंजरु शामिल थे।

इस आयोग का गठन भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन (सीमांकन) हेतु किया गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश के गठन के पश्चात् अन्य राज्यों द्वारा भी भाषा के आधार पर पुनर्गठन की माँग उठने लगी थी।

11. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए।

(Chap 1, Class-XII, New NCERT)

सूची-I (सिद्धांत/आधार)	सूची-II (उदाहरण)
A. विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण	1. भारत और पाकिस्तान
B. धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण	2. पाकिस्तान और बांग्लादेश
C. किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन	3. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
D. भौगोलिक आधार पर किसी देश के आंतरिक क्षेत्रों का सीमांकन	4. झारखंड और छत्तीसगढ़

कूट

- A B C D
(a) 1 2 3 4
(b) 2 1 3 4
(c) 1 3 2 4
(d) 2 3 4 1

➤ उत्तर (b)

व्याख्या सही सुमेलन A-2, B-1, C-3, D-4 है।

वर्ष 1971 के युद्ध के पश्चात् जाति और भाषागत आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण हुआ। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, जबकि पश्चिमी भाग, पाकिस्तान है।

वर्ष 1947 में धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया गया था, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को भारतीय राज्यों से अलग कर पाकिस्तान बनाया गया।

हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग कर एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। इन दोनों राज्यों के क्षेत्रों के सीमांकन का आधार राजनीतिक और प्रशासनिक था।

झारखंड को बिहार से तथा छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इन राज्यों के आंतरिक क्षेत्रों का सीमांकन भौगोलिक आधार पर किया गया था।

12. वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा, कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई?

(Chap 1, Class-XII, New NCERT) (MPPSC Pre 2021)

- (a) 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र
(b) 18 राज्य, 9 संघीय क्षेत्र
(c) 22 राज्य, 8 संघीय क्षेत्र
(d) 21 राज्य, 7 संघीय क्षेत्र

➤ उत्तर (a)

व्याख्या वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह सलाह दी थी कि मूल संविधान के अंतर्गत चार आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्रशासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। इन संस्तुतियों को भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया। लेकिन पुनः कुछ संशोधित परिणामों के साथ 1 नवंबर, 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया।

13. निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके गठन के अनुसार कालानुक्रम बनाएँ तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। (Chap 1, Class-XII, New NCERT)

1. हरियाणा
2. मेघालय
3. नागालैंड
4. गुजरात

कूट

- (a) 4 2 1 3 (b) 4 3 1 2
(c) 4 1 3 2 (d) 1 4 3 2

➤ उत्तर (b)